वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव : एक विवेचना

डा० पूजा सिन्हा
एसोसिएट प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग
डी०ए०वी० कालेज,
कानपुर

आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार आपस में जुड़ी हुई है उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। देशों के बीच तेजी से एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ वैश्वीकरण प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं क्योंकि अधिक सामान व सेवाएँ निवेश और प्रौद्योगिकी देशों के बीच चलती है। वैश्वीकरण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन तकनीक और निवेश आदि को लेकर खुले तौर पर पारस्परिक बातचीत एवं व्यवहार करता है। वैश्वीकरण विदेशी व्यापार एवं निजी और संस्थागत विदेशी निवेश को बढ़ाता है यह वास्तव में विदेशी व्यवार पर लगे सभी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाता है।

दीपक नैय्यर के अनुसार ''वैश्वीकरण आर्थिक गतिविधियों के राष्ट्र राज्यों की राजनीतिक सीमाओं से बाहर से विस्तार के रूप में की जा सकती है।''

भारतीय वैश्वीकरण के लक्ष्य –

1. **व्यापार का वैश्वीकरण** – इसका अर्थ अन्तराष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण को कम करना और आयात निर्यात संबंधित उदारीकरण नीति को अपनाना है। भारत सरकार से व्यापार के वैश्वीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उदारीकरण की नीति को अपना रही है। सरकार

नियन्त्रण से विदेशी व्यापार को उदारीकृत करने के लिए और स्वतंत्र ढंग में इसके विकास की अनुमति के लिए जुलाई 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन 22 प्रतिशत तक दो किश्तों में हुआ ताकि रुपया अपनी वास्तविक दर को पहचान सके। 1993–94 में व्यापार पर पूर्ण परिवर्तनशीलता को लागू किया गया। 1994–95 में चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनशीलता को लागू किया गया। आयातों और निर्यातों पर प्रतिबन्धों को कम किया यगा। आयात शुल्कों के क्वांटम को कम किया गया।

2. **निवेश का वैश्वीकरण** – इसका अर्थ विदेशी निवेश पर प्रतिबन्धों को हटाना और इसे आकर्षित करने के लिए छूटों को प्रदान करना है। 1991 में, विदेशी पूंजी निवेश की आज्ञा 51% तक 34 उच्च प्रथमिकता वाले उद्योगों में सरकार की पूर्व अनुमति के बिना दी गई। 1996 में, विदेशी निवेश की आज्ञा 74% तक 9 उद्योगों में दी गई। एक गैर–प्रवासी भारतीय द्वारा अंशों के अन्य गैर–प्रवासी भारतीयों के साथ स्थानान्तरण पर प्रतिबन्धों को वापस ले लिया गया। विदेशी निवेशकों को बाजार मूल्यों पर अनिवेशित इक्विटियों की आज्ञा दी गई। बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने देश में निर्यात उन्मुख इकाईयों को स्थापित करने के लिए कई छूटें प्रदान की। विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की सथापना विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई।

3. **वित्त का वैश्वीकरण** – आर्थिक नीति 1991 के अनुसार उदारीकरण नीति को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त का सम्बन्ध विदेशी सरकारों, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों व्यावसायिक ऋणों, अनुदानों और निवेश के साथ होता है। इसमें विदेश वित्तीय संस्थानों और विदेशी बैंकों को भी शामिल किया जाता है। विदेशी विनिमय अधिनियम द्वारा शासित कम्पनियों को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना जमा को स्वीकारने या उधार लेने की आज्ञा

दी जाती है। गैर प्रवासी भारतीयों की जमा को गतिवान करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। विदेशी संस्थानिक निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार में निवेश की आज्ञा दी गई। भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे भारतीय स्टेट बैंक, विदेशी पूंजी को गतिवान करने के लिए India Resurgent Bonds को बेचता है।

वैश्वीकरण के प्रचल –

वैश्वीकरण के प्रायः चार प्राचल होते हैं जो निम्न है :–

- देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करके अथवा कम करके वस्तुओं को स्वतन्त्र प्रवाट की आज्ञा।
- देशों के बीच पूंजी के प्रवाह के लिए वातावरण की रचना।
- शिल्प शस्त्र के स्थानान्तरण के स्वतन्त्र प्रवाह की आज्ञा।
- विश्व के देशों में श्रमिकों के स्वन्त्र आने व जाने के लिए वातावरण की रचना।

वैश्वीकरण के उद्देश्य –

- **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग** – अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक सम्बन्ध बनाए रखने हेतु विश्व के सदस्य देशों का आपसी सहयोग बेहद आवश्यक है। इसके अन्तर्गत एक देश दूसरे देश को सहयोग देकर सीमा के अंदर व्यापार से सम्बन्धित कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है।
- **आर्थिक समानता** – वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्यों में दूसरा है देश में फैली आर्थि असमानताओं को दूर करना होता है। आर्थिक असमानताओं को दूर करने से विकासशील देशों को विकसित देश की श्रेणी में लाना आसान हो जाता है।

- **विश्व–बंधुत्व की भावना का विकास** – वैश्वकरण से विश्व भर विश्वबंधुत्व की भावना विकसित होती है। यदि किसी देश में कोई प्राकृतिक या अप्राकृतिक विपत्ति आती है तो उस देश को अन्य विकसित देशों से यथासम्भव आर्थिक व मानवीय सहयोग मिलता है। इस प्रकार वैश्वीकरण को स्वीकार करने का यह भी एक प्रमुख उद्देश्य होता है।
- **विकास हेतु नवीन साझेदारी** – विश्व के सदस्य देशों को एक साथ करने एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाये रखने के लिए वैश्वीकरण का निर्माण किया गया है। वैश्वीकरण के अन्तर्गत समस्त देशों की आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक आदि शक्तियों को एक साथ विकास हेतु प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ वैश्वीकरण का मूल्य सिद्धान्त विश्व में सभी देशों के बीच व्यापार एवं आदान–प्रदान को बढ़ाना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव –

वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृतियों का संचार, पविहन और व्यापार का वैश्विक नेटवर्क का माध्यम हो गई है – भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं –

सकारात्मक प्रभाव –

- नई आर्थिक नीति का आगमन – वैश्वीकरण नीति जिसे नई आर्थिक नीति, 1991 के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह संकट से बाहर आने का उपाय होता है। अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और वैश्वीकरण करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए थे –
    - अवमूल्य : भुगतान की समस्या के समाधान के लिए भारतीय मुद्रा का 18 से 19% तक अवमूल्यन किया गया।

- विनिवेश : एलपीजी मॉडल को सुचारु बनाने के लिए कई सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को बेच दिया गया।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति : एफ.डी.आई. को बीमा (26%) रक्षा उद्योग (26%) आदि जैसे कई क्षेत्रों में अनुमति दी गई थी।
- एनआर आई योजना : विदेशी निवेशकों को जो सुविधाएँ उपलब्ध थीं, वे भी एन.आर.आई. दी गई।

- **कृषि क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव** – कृषि क्षेत्र ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है जिसके आपसपास सामाजिक–आर्थिक विशेषाधिकार और अभाव घूमते हैं और इसकी संरचना में किसी भी बदलाव का सामाजिक इक्विओ के मौजूदा पैटर्न पर एक समान प्रभाव पड़ने की सम्भावना होती है। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के लिए अनिवार्य रूप बाजार के सरकारी नियंत्रण को धीरे–धीरे समाप्त करने, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों का निजीकरण करने, और मुक्त व्यापार को सक्षम करने के लिए निर्यात सब्सिडी और आयात बाधाओं को कम करने के लिए सुधारों की मांग की गई।

  वैश्वीकरण ने इसमें मदद की है :–

  - जीवन स्तर को ऊपर उठाना।
  - गरीबी को कम करना।
  - खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - उद्योग और सेवाओं के विस्तार के लिए व्यापक बाजार तैयार करना।
  - राष्ट्रीय आर्थिक विकास में पर्याप्त योगदान देना।

- **औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभाव** – भारतीय उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभाव तब शुरू हुए जब सरकर ने 1990 के दशक की शुरुआत में देश के बाजारों को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। भारतीय उद्योग का वैश्वीकरण अपने विभिन्न क्षेत्रों जैसे – इस्पात, दवा, पेट्रोलियम, रसायन, कपड़ा, सीमेंट, खुदरा और बीपीओ में हुआ। उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभाव का लाभ यह है कि विदेशी कम्पनियाँ अपने साथ अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकी लाती है और इससे भारतीय उद्योग को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में मदद मिली।
- **वित्तीय क्षेत्र पर प्रभाव** – आर्थिक क्षेत्र का सुधार आर्थिक उदारीकरण की दिशा में भारत के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है हाल के आर्थिक उदारीकरण के उपायों ने हमारे घरेलू बाजार में प्रवेश करने के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धियों के द्वार खोल एि हैं। नवाचार अस्तित्व के लिए जरूरी हो गया है। वित्तीय मध्यस्थ अपने पारम्परिक दृष्टिकोण से बाहर आ एग है और वे अधिक क्रेडिट जोखिमों को मान्झों के लिए तैयार है। भारत में वित्तीय सेवा उद्योग का देश में फैले लाखों भावी निवेशकों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवीन उत्पादों की पेशकेश करके आने वाले वर्षों में एक बहुत ही सकारात्मक और गतिशील भूमिका निभाती है।

अन्य प्रभाव –

- इन उद्योगों में निवेश + नई नौकरियाँ,
- कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कम्पनियाँ का समृद्धि।
- भारतीय कम्पनियों को विदेशी कम्पनियों के साथ सफल सहयोग से लाभ हुआ। उदाहरण – टाटा मोटर्स, इंफोसिस।

- तकनीकि विकास + व्यापार की मात्रा में वृद्धि को विश्व की जीडीपी में वृद्धि होगी।
- इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार + सुदूरतम ग्रामीण क्षेत्रों तक बुनियादी ढाँचा > ग्रामीण विकास समावशे विकास।

नकारात्मक प्रभाव –

- व्यापार घाटा जो अविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मामले में सबसे अधिक नुकसान पहुँचाता है ओर विकसित और अविकसित अर्थव्यवस्था के बीच अंतर को बढ़ाता है।
- कृषि क्षेत्र में उतना सुधार नहीं हुआ जिनता कि सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में मंहगा मामला बनता जा रहा है। राज्यकृषि में अपनी व्यापक, भूमिका वापस ले रहा है।
- टिकाऊ विकास नहीं, पर्यावरण, वन, वन्य जीव आदि की बढ़ती लापवाही पर विकास।
- पारम्परिक सेवा प्रदाताओं को विकास/उदाहरण परांठा, लस्सी, समोसा, कचौड़ी की जकर मैकडोनाल्ड, के0एफ0सी0, पिज्जा हट आदि।

निष्कर्ष –

21वीं सदी में दुनिया पर राज करने के लिए अर्थशास्त्र विशेषज्ञ और दुनिया भर में किए गए विभिन्न अध्ययनों में भारत और चीन की परिकल्पना की गई है। निष्कर्ष निकालने के लिए हम कह सकते है कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर जो आधुनिकीकरण दिखाई दे रहा हैं वह वैश्वीकरण की ही देन है। वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिल रहे है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1991 से एक लम्बा समय हो गया है जिसमें परिणामस्वरूप हमारे देश की उन्नति हुई है।

संदर्भ ग्रन्थी सूची

- भारतीय अर्थव्यवस्था, दत्त और सुंदरम
- भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रा ओर पुरी
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- http ps://byjus.com
- https://ncert.nic.in
- https:// www.hindigyan.com
- https://www.vedantu.com
- https://ijrrssonline.in